RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

दैनिक

क्रांति समय

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 253, शनिवार, 19 अक्टुबर, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आदिवासी कल्याण के मुद्दे पर शाह ने पूछा राहुल गांधी से सवाल

गढ़चिरौली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आदिवासी कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और पार्टी नेता राहुल गांधी से पूछा कि उनकी चार पीढ़ियों ने 70 साल के शासन के दौरान जनजातीय समुदाय के लिए क्या किया। पूर्वी महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित गढ़चिरौली के अहेरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि नक्सली विकास के विरोधी हैं तथा मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में समस्या पर लगाम कसी है। भाजपा अध्यक्ष शाह ने कहा कि कांग्रेस नीत सरकारों ने वोट-बैंक की राजनीति के लिए संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि अंततः मोदी सरकार ने इस विवादास्पद प्रावधान को समाप्त किया जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। शाह ने आदिवासी बहुल जिले में आयोजित रैली में राहुल गांधी के लिए सवाल किया, आपकी चार पीढ़ियों ने 70 साल तक देश पर शासन किया, आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? भाजपा अध्यक्ष ने गांधी और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधते हुए उनसे जिले में तथा महाराष्ट्र में किये गये उनके कामकाज का हिसाब देने को कहा जहां 1999 से 2014 तक 15 साल तक कांग्रेस-राकांपा सरकार रही।

शर्मसारः वायुसेना अधिकारी के पिता की पिटाई कर पोती कालिख, जबरन खिलाया मल-मूत्र

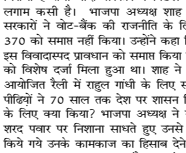

नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रेम विवाह कर लेने से खफा लड़की के उद्योगपति परिजनों ने वायुसेना अधिकारी के पिता की निर्मम पिटाई ही नही की बल्कि उन्हे मल मूत्र खिलाया और उसके ऊपर खुलेआम पेशाब भी किया। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की पुलिस ने भारी दबाव के बाद आखिरकार प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नेहरु नगर निवासी योगराज अग्रवाल के ग्वालियर में पदस्थ वायुसेना अधिकारी पुत्र अंकित अग्रवाल ने उद्योगपति बंशी अग्रवाल की मेडिकल की पढाई कर रही बेटी से आपसी रजामंदी से विवाह कर लिया। परिजनों के अनुसार लड़की स्वयं भागकर अंकित के पास 10 अक्टूबर को पहुंची और ग्वालियर में ही विवाह किया । इसकी जानकारी मिलने के बाद से ही बंशी अग्रवाल खफा हो गया। योगराज अग्रवाल भिलाई तीन से कल अपने आफिस के लिए कार से निकले थे कि रास्ते में बंशी ने अपनी कार को लगाकर उनकी कार को रोक दिया। उसके बाद बंशी के साथ विनोद, आशीष गुप्ता समेत पांच -छह कर्मचारियों ने उन्हे कार से बाहर निकाला और उनकी टी शर्ट उतारकर पीटते रहे। इस दौरान मलमूत्र भी खाने को मजबूर किया और चेहरे पर पेशाब भी कर दिया। उसके चेहरे पर कालिख भी पोत दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपी उद्योगपति भिलाई अग्रवाल समाज का अध्यक्ष भी है। आर्थिक रूप से काफी मजबूत होने के कारण आरोपी के खिलाफ काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।फिलहाल पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नही की है और अधिकारी मामले की जांच जारी होने की बात कर रहे है।

दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में सफाईकर्मी लगा रही मरीज को इंजेक्शन, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मरीज को एक महिला सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगाती हुई दिखाई दे रही है। यह मामला दिल्ली के हरी नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयू) का है। वीडिया में साफ दिख रहा है कि महिला सफाईकर्मी अपने एक हाथ से मरीज की कलाई पकड़े हुए, उसके दूसरे हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है और वह उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही है। जब उसे पता चल जाता कि वार्ड में मौजूद शख्स उसका वीडियो बना रहा तब वो रुक गई। सरकारी अस्पताल से जुड़ी इस वीडियो को देख हर कोई हैरान रह गया है। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है। इस बारे में अस्पताल के एम.डी का कहना है, कि उनके पास भी वीडियो आया है जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन को जांच के आदेश दिए जा चुके है। इसके लिए ऑन ड्यूटी दोषी नर्स को सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि मरीज की तरफ से कोई शिकायत नही आई है, लेकिन मामले की जानकारी मिलते उन्होंने कारवाई शुरू कर दी है। एम.डी से मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो ऑर्थो वार्ड नंबर 4 का है, लेकिन कब का है इसकी जांच की जा रही है। इस लापरवाही में जिसकी गलती है उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी।

भारत की बढ़ी ताकत, बोफोर्स से भी घातक तोप 'धनुष' सेना में शामिल

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने संभावित खतरों को देखते हुए बोफोर्स से भी खतरनाक तोप धनुष को अपने आर्टिलरी विंग में शामिल कर लिया है। धनुष तोप स्वीडिश तोप बोफोर्स का स्वदेशी ऊत संस्करण है। स्वदेश में निर्मित इस तोप की मारक क्षमता इतनी खतरनाक है कि 50 किलोमीटर की दूरी पर बैठा दुश्मन पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। बुधवार को भारतीय सेना के आर्मी कोर कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जानकारी दी गई। इस तोप की मारक क्षमता को घातक बनाने के लिए अमरीका के खतरनाक प्रिसिजन गाइडेड एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनीशन को सेना में शामिल किया है। एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनीशन तोप में इस्तेमाल होने वाला आधुनिक गोला-बारूद है खतरों के बढ़ते स्तर को देखते हुए सेना ने अमेरिका से एक्सकैलिबर गोला- यह 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद सकता है। यह जीपीएस सिस्टम से लैस है, जो लक्ष्य को पहचानकर उसे खत्म कर देता है। इसमें लगे 100 फीसदी कलपुर्जे स्वदेशी हैं। नेवीगेशन आधारित साइटिंग सिस्टम, ऑटो लेइंग सुविधा, ऑनबोर्ड बैलिस्टिक गणना और दिन-रात में सीधी फायरिंग की सुविधा, बॉल बैग और बाई माड्यूलर सिस्टम दोनों का इस गन में प्रयोग किया गया है। जिससे इसकी रेंज बढ़ गई है।

वीर सावरकर मामले पर कैलाश का दिग्गी को करारा जवाब, कहा- उन्हें मिर्ची लगना स्वाभाविक है

भोपाल(एजेंसी)।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जारी किए गए घोषणापत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। जिसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 'जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप है भाजपा उसे भारत रत्न देने की बात कर रही है'। दिग्गी के इस बयान पर अब बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा है कि 'नेहरू जी, इंदिरा जी ने खुद को ही भारत रत्न दे डाला था लेकिन इन महापुरुषों को भारतरत्न देने में आपकी पार्टी की सरकारों ने पचासों साल लगा दिये। वीर सावरकर को भारतरत्न मिलने की बात पर आपको मिर्ची लगना स्वाभाविक है। सावरकर का जीवन देश के लिये था, उनका जीवन देशवासियों के लिये प्रेरणादायक है पर दिग्विजय सिंह की कांग्रेस पार्टी को तो हर देशभक्त से चिढ़ है चाहे वो सुभाषचंद्र बोस हों, सरदार पटेल हों या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वीर सावरकर के जिंदगी के दो पहलू थे। पहले पहलू में अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद लौटने पर स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी। जबकि दूसरे पहलू में उनका नाम गांधी की हत्या का षड़यंत्र रचना' शामिल था। दिग्विजय के इसी बयान के बाद से सियासी गलियारों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई, और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह डाला कि दिग्विजय सिंह सावरकर के पैरों की धूल भी नहीं हैं।

15 साल से चल रही है वीरप्पन के 3000 करोड़ के खजाने की खोज, रखता था स्पेशल कोडवर्ड

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों की पुलिस, सुरक्षा बलों और प्रशासन के लिए सिरदर्द बने चंदन के कुख्यात तस्कर वीरप्पन को आज के दिन मौत के घाट उतारा था। हाथीदांत के लिए सैकड़ों हाथियों की जान लेने वाले और करोड़ों रूपए के चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन ने तस्करी के अपने अभियानों को अंजाम देने के दौरान करीब डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की जान ली और उनमें से आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने हाथी दांत, चंदन की तस्करी और किडनैपिंग के जरिये करीब 3 हजार करोड़ की दौलत जुटाई थी। कर्नाटक और तमिलनाडु एसटीएफ ने संयुक्त मिशन चलाकर उसका खात्मा कर दिया, लेकिन एसटीएफ या सरकार को वीरप्पन का खजाना और हथियारों का जखीरा आज तक नहीं मिल पाया है। इस खजाने को ढूंढने के लिए कई गांव वाले लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल किसी के हाथ सफलता हाथ नहीं लगी है। एसटीएफ के आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 18 अक्टूबर 2004 को खूंखार चंदन तस्कर वीरप्पन को एनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया गया था। बताया जाता है कि इस खजाने को वीरप्पन ने कर्नाटक व तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले सत्यमंगलम के घने जंगलों में गड्ढे खोदकर दबाया था। इस इलाके में पैसे, जेवरात व अन्य कीमती जीचें जमीन में दबाकर रखने का चलन काफी पुराना है। गांव वाले बैंक या घर में पैसे या कीमती सामान रखने की बजाय यही तरीका अपनाते हैं। तमिल मैगजीन नक्कीरन के संपादक आर गोपाल (जिन्होंने वीरप्पन का इंटरव्यू लिया था) बताते हैं कि खूंखार जंगल के बीचोंबीच कई जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे खोदे जाते थे और उनके अंदर अनाज के साथ 500 व 1000 के नोटों का बंडल पॉलिथीन में रखकर दबाए गए हैं। क्योंकि उनमें कीड़े न लगें। साथ ही साथ वीरप्पन को इस जंगल के चप्पे-चप्पे की जानकारी थी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, रविदास मंदिर के लिए उसी जगह देंगे जमीन

नई दिल्ली(एजेंसी)।

दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर को गिराए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने रविदास मंदिर के लिए जमीन देने का वादा किया। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए केंद्र सरकार उसी जगह पर 200 वर्ग मीटर की जमीन दक्षिणी दिल्ली में उसी जगह देगी जहां मंदिर को तोड़ा गया था। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि भक्तों की एक समिति को मंदिर निर्माण के लिए सरकार जमीन देगी। कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव को रिकॉर्ड में लिया, अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने पुलिस बल के साथ तुगलकाबाद के वन क्षेत्र में स्थित गुरु रविदास जी महाराज के मंदिर को तोड़ दिया था। डी.डी.ए. का दावा है कि मंदिर उसकी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था जिसका मामला अदालत में सुना गया और अंत में इसे हटाने का आदेश हुआ। मंदिर तोड़े जाने की खबर से संत रविदास के अनुयायियों में रोष फैल गया । एडवोकेट सतपाल बिरदी, एडवोकेट इंद्रजीत सिंह, नैशनल शैड्यूल्ड कास्ट अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैथ, आदि धर्म मिशन खुरालगढ़ साहिब के संत सतविन्द्र सिंह हीरा के अनुसार तुगलकाबाद स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर 600 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की जमीन दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी ने दी थी। सिकंदर लोधी हर हाल में श्री गुरु रविदास जी का धर्मांतरण कर उन्हें मुस्लिम बनाना चाहता था लेकिन जब किसी भी तरह वह सफल नहीं हो पाया तो बादशाह के आदेश पर श्री गुरु रविदास महाराज को जेल में डाल दिया गया। इसके जवाब में चंबर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया था। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोधी ने गुरु महाराज को छोड़ दिया।यही नहीं, गुरु महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित होकर स्वयं बादशाह सिकंदर लोधी ने 800 कनाल (लगभग 12 बीघा और 7 बिस्वा) जमीन उपहार स्वरूप दी थी। जिस पर गुरु महाराज के अनुयायियों ने 600 साल पहले मंदिर बनाकर सत्संग शुरू किया था। एडवोकेट बिरदी ने बताया कि 1959 में स्वयं उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम इस मंदिर में गए और मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। यही नहीं, दिल्ली रैवेन्यू रिकार्ड में इस मंदिर का इंदराज दर्ज है। 1964 में इस मंदिर की जमीन को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले लिया और कोर्ट में केस चला गया।

केजरीवाल सरकार ने केंद्र से की और प्याज की मांग, बढ़ाई मोबाइल वैनों की संख्या

नई दिल्ली(एजेंसी)।

दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने सस्ती प्याज की आपूर्ती के लिए केंद्र सरकार से प्याज की मांग की है। इसके साथ ही हुसैन आला अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक वार्ड में प्याज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मोबाइल वैन की संख्या 80 से बढ़ाकर 400 करने का निर्णय लिया है। इमरान हुसैन ने भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने नेफेड को निर्देश देने का अनुरोध किया है, ताकि दिल्ली में मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा बिक्री करने के लिए केंद्रीय बफर से पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को प्याज की आपूर्ति की जाए। पत्र में कहा गया है कि अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन 10 ट्रक प्याज दिल्ली सरकार को दी जाए। बता दें कि प्याज के दामों में अचानक उछाल आने के बाद से नेफेड से प्याज खरीद कर दिल्ली वालों को कद दामों में उपलब्ध करा रही है। ये प्याज राशन की दुकानों और दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही 70 मोबाइल वैनों के जरिए जनता तक पहुंचाया जा रहा है। अब सरकार इन मोबाइल वैनों की संख्या बढ़ाकर 400 करने जा रही है। वहीं प्याज की किल्लत होने के चलते केंद्र सरकार से अगले 10 दिनों में प्रति दिन 10 ट्रक प्याज की मांग भी की गई है। दिल्ली सरकार 23.90 रुपये में दिल्लीवासियों को प्याज उपलब्ध करा रही है, जबकि अन्य राज्यों में प्याज 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है।

विधानसभा चुनावः महाराष्ट्र में 3237 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर

औरंगाबाद(एजेंसी)।

महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में 3237 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच चुका है। चुनाव आयोग ने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग द्वारा जारी किये आधिकारिक बयान के अनुसार सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,79,895 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), 1,26,505 नियंत्रण इकाइयां और 1,35,021 वीवीपैट मशीनों के साथ अतिरिक्त मशीनों का उपयोग किया जाएगा। चुनाव में कुल 8,98,39,600 मतदाता भाग लेंगे जिनमें 4,28,43,635 महिलाएं, 3,9600 दिव्यांग मतदाता, 2634 ट्रांसजेंडर और 1,17,581 सर्विस मतदाता शामिल हैं। मतदाता राज्य के 95473 मुख्य मतदान केंद्रों और 1188 सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल 96661 केंद्रों पर अपना वोट डालेंगे। इसके अलावा आयोग ने राज्य में 352 'सखी मतदान केंद्रों की भी स्थापना की है, जिसका प्रबंधन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। दिवयांग, वृद्ध एवं बीमार मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किये गये हैं और इनके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य में चुनाव अधिकारियों सहित 6.5 लाख से अधिक विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बयान में कहा गया है कि आयोग ने मतदाताओं के बीच चुनाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। जागरूकता अभियान में वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, अभिनेताओं, खेल जगत की हस्तियों, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, विशेष रूप से विकलांग श्रमिकों और ट्रांसजेंडर श्रमिकों ने भी भाग लिया। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक विशेष ऐप भी लॉन्च किया है तथा ईवीएम के परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया है। बयान में कहा गया कि मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों का विवरण आयोग के वेब साइट पर मिलेगा।

'यात्रियों में देशभक्ति पैदा करने के लिए 26 रेलवे स्टेशनों पर लगाया जाएगा तिरंगा

भुवनेश्वर(एजेंसी)।

पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने यात्रियों में देशभक्ति पैदा करने के लिए जोन के 26 रेलवे स्टेशनों पर 100 फुट ऊंचे स्तंभों पर राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा लगाने का फैसला किया है। रेलवे ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यात्रियों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करने के रेल मंत्रालय के निर्देश के तहत रेल मुख्यालयों, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय लिया गया है। भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज पहले ही लगाए जा चुके हैं। बयान में कहा गया कि तिरंगा लगाने के लिए प्रस्तावित अन्य स्टेशनों में खुर्दा रोड रेल संभाग में 13, वाल्टेयर में सात और संबलपुर में छह स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर दृश्यता, स्थान की उपलब्धता और अन्य सुरक्षा उपाय को देखते हुए राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किए जाएंगे। खुर्दा रोड संभाग के अंतर्गत प्रस्तावित स्टेशन पुरी, कटक, भद्रक, जाजपुर, क्योंझर रोड, केंदुझर, अंगुल, ढेंकानाल, खुर्दा रोड, खुर्दा शहर, नयागढ़ शहर, ब्रह्मपुर, छतरपुर और पारादीप हैं। संबलपुर संभाग के अंतर्गत संबलपुर, बारगढ़ रोड, भवानीपटना और महासमुंद रेलवे स्टेशनो, जबकि वाल्टेयर संभाग के अंतर्गत कोरापुट, रायगढ़, पारालाखेमुंडी, श्रीकाकुलम रोड, विजयनगरम, जगदलपुर और दंतेवाड़ा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि संबंधित स्टेशन प्रशासन और आरपीएफ चौकी ध्वज की सुरक्षा, संरक्षा और रखरखाव का काम देखेंगे।

सावरकर को भारत रत्न देना भगत सिंह का अपमान : कन्हैया

औरंगाबाद(एजेंसी)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता एवं जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार विनायक सवारकर को भारत रत्न से सम्मानित करती है, तो उसे इसी पुरस्कार के लिए शहीद भगत सिंह के नाम की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। कुमार ने आमखास मैदान में औरंगाबाद मध्य विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार ए.डी.वी. अभय टकसाल के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश करेगी, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह का अपमान है। उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। भाकपा नेता ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने निजामों के शासन को मराठवाड़ा से समाप्त करने के लिए शुरू किये गये मुक्ति संग्राम में भाग लिया था और पार्टी हमेशा लोगों की भलाई के मुद्दे पर लड़ती रहेगी। औरंगाबाद में जातिवाद की राजनीति समाप्त हो गयी है। उनकी पार्टी यहां 35 विभिन्न मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा अनुच्छेद 370 की मुद्दे उठा रही है और किसान, बेरोजगारी, सड़क, जल संकट जैसे कई बुनियादी मुद्दों को दर किनार कर रही है। नैया ने मतदाताओं से जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मतदान नहीं करने की अपील करते हुए ।

संपादकीय

तुलागी पर चीन का कब्जा

अपनी आर्थिक ताकत को कूटनीतिक व सामरिक बढ़त में बदलने की चीन की कोशिशें अब नया रंग दिखा रही हैं। चीन ने प्रशांत महासागर में सोलोमन के एक पूरे द्वीप को ही 75 साल के पट्टे पर ले लिया है। सोलोमन एक ऐसा देश है, जो तकरीबन 900 छोटे-बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। अगर नक्शे पर देखें, तो ऑस्ट्रेलिया के आगे पापुआ न्यू गिनी के उस पार कुछ छोटी-छोटी बिंदियां दिखाई देती हैं, यही सोलोमन द्वीप समूह है। इसी का एक छोटा सा द्वीप तुलागी है, जिसे चीनी कंपनी चाइना सैम इंटरप्राइजेज ने पट्टे पर लिया है। इस द्वीप पर कितनी आबादी है, यह तो ठीक से नहीं पता, लेकिन अभी तक वहां कुछ होटल व रिजॉर्ट हैं। जाहिर है, वहां दुनिया भर के अमीर छुट्टियां मनाने के लिए जाते होंगे, पर अब माना जा रहा है कि जल्द ही यह जगह चीन का सैनिक या असैनिक अड्डा होगी। लीज की शर्तों में चीन की कंपनी को औद्योगिक विकास या जैसी जरूरत वह समझे, उस हिसाब से इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। अभी यह साफ नहीं है कि वहां होने वाली गतिविधियों पर सोलोमन का कोई नियंत्रण रहेगा या नहीं।

महत्वपूर्ण यह है कि चीन ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। अभी तक सोलोमन दुनिया के उन चंद देशों में था, जो ताईवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं। उसके ताईवान से राजनयिक संबंध भी थे। चीन ने पिछले ही महीने इस पूरे समीकरण को पलट दिया था। पिछले महीने खबर आई कि सोलोमन ने ताईवान से अपने रिश्ते पूरी तरह तोड़कर चीन से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। इसे ताईवान और अमेरिका, दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा झटका माना गया था। लेकिन तब यह नहीं सोचा गया था कि यह पहला कदम है और चीन के इरादे इससे कहीं आगे जाने के हैं। वैसे तो सोलोमन द्वीप समूह हमेशा से ही सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहा है। यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में ही इसके सामरिक महत्व को पहचान लिया गया था। यह माना जाता है कि अमेरिका इस समय प्रशांत महासागर में चीनी विस्तारवाद को रोकने के लिए कमर कसे हुए है। इसमें उसके दो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं- जापान और ऑस्ट्रेलिया। सोलोमन उस समुद्री रास्ते पर पड़ता है, जो जापान को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। इसी रास्ते पर ताईवान भी है। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ने चीन को घेरने की वाकई कोई सामरिक तैयारी की है, अभी इसकी सारी बातें सिर्फ संभावनाओं के आकलन के स्तर पर ही चल रही हैं। जबकि चीन ने किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए अपनी चाल चल दी है।

और कुछ न भी हो, तो तुलागी पर चीन का कब्जा दुनिया के तनाव को बढ़ाने का काम तो करेगा ही। और इस तनाव का असर कम या ज्यादा भारत के ऊपर भी पड़ेगा ही। हालांकि भारत को चीन ने अभी तक जो चिंताएं दी हैं, वे इससे कहीं ज्यादा हैं। एक तरफ तो चीन श्रीलंका के एक बंदरगाह पर काबिज हो चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह उसके कब्जे में है ही, साथ ही वहां तक जाने की एक बड़ी सड़क भी उसी के पास है। यही नहीं, इन्फास्ट्रक्चर विकास के नाम पर उसने नेपाल में भी अपने पांव जमा लिए हैं। तुलागी द्वीप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना बड़ा सिरदर्द नहीं होगा, जितनी ये सारी चीजें भारत के लिए हैं।

कश्मीर में हिंसा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हफ्ते भर के अंदर आतंकवादी हमले की तीन वारदात से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां किस तरह की दुश्वारियां दरपेश हैं। खासकर पोस्टपेड सुविधा पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद से आतंकवादी घटनाओं में तेजी चिंता का सबब है। आतंकवादियों के निशाने पर गैर कश्मीरी ही रहे हैं। पहले शोपियां में एक गैर कश्मीरी सेब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उससे पहल शोपियां में ही राजस्थान के ट्रक ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर पुलवामा में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की हत्या कर दी गई। यानी दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी न केवल सक्रिय हैं बल्कि वहां उनके रहनुमा भी मौजूद हैं जो उनके बचाव के लिए हरसंभव उपायों से लैस हैं। पहले भी घाटी का यह दक्षिणी भाग आतंकवादी हिंसा के मामले में सबसे आगे था। एक तरफ सरकार राज्य के लोगों की सुविधा के वास्ते वो सभी जतन कर रही है, जिससे वहां अमन की बयार बहे साथ ही जनजीवन पटरी पर भी लौटे। मगर हाल की कुछ घटनाओं को देखते हुए लगता है, वहां शांति की गुंजाइश में थोड़ा विलंब है। वैसे सरकार की कोशिश यही है कि वहां जल्द-से-जल्द उन बंदिशों पर से रोक हटा ली जाए, जिससे सूबा विकास की पटरी पर सरपट दौड़ सके। पिछले 72 दिनों से जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया है पाकिस्तान इसी साजिश में लगा है कि कश्मीर के बहाने भारत में अशांति फैलाई जाए। हालांकि यहां आतंक फैलाने का काम वह काफी अरसे से कर रहा है मगर इस वक्त उसकी बौखलाहट और सनक चरम पर है। पहले सीमा पार से बमबाजी फिर पंजाब में ड्रोन की मदद से हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप पहुंचाने से पाकिस्तान की करतूतों का पता चलता है। वह हर हाल में इस प्रयास में है कि कश्मीर में केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल परवान नहीं चढ़े। यही वजह है कि वह कभी चीन तो कभी संयुक्त राष्ट्र तो कभी तुर्की का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाता है। हालांकि हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार की वहां की जनता को दी जाने वाली ढील पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। सरकार के लिए यह परीक्षा का समय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कश्मीर में बहुत जल्द हिंसा का दौर खत्म होगा और शांति बहाल होगी।

परिधि/विशाल तिवारी

जमीनी हालात तो सुधारिए

अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और उसे बढ़ावा देना अच्छा विचार है, बशर्ते वो व्यावहारिकता की सीमा में हो। व्यावहारिकता की सीमा क्या और कितनी हो ये समझ पर निर्भर है। वर्तमान सरकार का संस्कृत अनुराग जगजाहिर है। बता दें कि इस बार भाजपा के 40 लोक सभा सांसदों ने संस्कृत में शपथ ली थी। सरकार के अनुराग को विस्तार देते हुए अब सांसदों को संस्कृत प्रशिक्षण देने की पहल हुई है। संघ से जुड़ी संस्कृत भारती के इस संबंध में प्रस्ताव को लोक सभा अध्यक्ष ने मंजूरी भी दे दी है। प्रस्ताव में संसद सत्र दौरान संस्कृत की पाठशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें सांसद अपनी सहूलियत के हिसाब से भाग ले सकेंगे। यहां दो प्रश्न उठते हैं। पहला उपयोगिता और दूसरा सहभागिता। बतौर भाषा संस्कृत की उपयोगिता बेहद सीमित है और यह प्रतीकात्मक ज्यादा है। वहीं सहभागिता के लिहाज से देश की सबसे बड़ी पंचायत में उपलब्ध समय बेहद सीमित है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा कि संसद में प्रति मिनट की कार्यवाही पर ढाई लाख से ज्यादा का खर्च आता है। इसके अलावे आज एक औसत सांसद पर 15 लाख से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी है। अन्य विधायी कार्य अलग हैं। ऐसे में जो सांसद संस्कृत कार्यशाला में सहभागिता करेंगे, उसके साथ वो कितना न्याय कर पाएंगे, इस पर संशय है। इससे तो बेहतर होता कि सांसदों के प्रबंधन और नीति निर्माण को सहज बनाने के लिए देश में मौजूद बेहतर प्रबंधन और नीति विशेषज्ञों से रू-ब-रू कराया जाता। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती। संसद में उचित सवाल उठाने से लेकर अपने क्षेत्र में योजनाओं को लागू करने और समस्याओं को हल करने में सहयोग मिलता। देशभर के संस्कृत विद्यालयों और विविद्यालयों की स्थिति कितनी दारूण है और वहां कार्यरत अध्यापकों को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, यह तय किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा इस ओर अगर संस्था की नजरे इनायत हो तो यह हर दृष्टि से बेहतर होगा। संस्कृत की दयनीय हालत के लिए हर कोई दोषी है; चाहे वह सरकार हो कि संस्थान। चुनांचे मूल समस्या पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

सुनवाई ही एक नजीर बन गई

विजय हंसारिया

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसले का इंतजार हो रहा है। लगातार 40 कार्यदिवसों में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आई तमाम अपीलों को सुना। दिनों के हिसाब से यह देश की दूसरी सबसे लंबी सुनवाई रही। इससे पहले केशवानंद भारती मामले में शीर्ष अदालत 68 दिनों तक बैठी थी। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले को इसलिए इतनी अहमियत दी गई, क्योंकि अयोध्या के 2.77 एकड़ विवादित स्थल पर मालिकाना हक को अदालत ने एक संवेदनशील मसला माना। देखा जाए, तो ऐसे मसलों की सुनवाई इसी तरह होनी चाहिए। संविधान पीठ को पांचों दिन बैठकर दलीलें सुननी चाहिए और मामले को न्याय तक पहुंचाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की यह खासियत है कि वह जल्दबाजी में कोई सुनवाई नहीं करती। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा समय देती है। निजता के अधिकार मामले में ही शीर्ष अदालत तकरीबन 30 दिनों तक सभी पक्षों को सुनती रही। इसमें लगभग छह महीने का वक्त लगा। तब हफ्ते में तीन दिन इस मामले की सुनवाई होती थी। उस वक्त संविधान पीठ में शामिल न्यायाधीश दूसरे मामले भी सुनते थे। नतीजतन, टुकड़े-टुकड़े में सुनवाई होती रही। एक बेंच साढ़े दस बजे बैठती थी, तो दूसरी सवा ग्यारह बजे; दो बजे एक अलग बेंच, तो ढाई बजे संविधान पीठ। बेशक इस तरीके पर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, पर अदालत की मंशा अनुचित नहीं कही जाएगी। जब कोई फैसला देश-समाज पर व्यापक असर डालने वाला हो, तो अदालती प्रक्रिया में थोड़ी-बहुत फेरबदल की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आनन-फानन में सुनवाई कर दी जाए। राम जन्मभूमि मामले में ही यह सवाल उठाना गलत होगा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई चूंकि अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इसके निपटारे में जल्दबाजी की गई। पिछले करीब आठ वर्षों से यह मसला शीर्ष अदालत में लंबित है। फिर, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के लिहाज से 40 दिन कम भी नहीं होते। यह सब कुछ मुकदमे की अहमियत देखकर तय किया जाता है। यहां कुछ मुकदमों की सुनवाई मिनटों में खत्म होती है, कुछ की घंटों में, तो कुछ को दिनों में। तभी एक निष्पक्ष फैसला हमारे सामने आता है।

अदालत ने इस विवाद को मध्यस्थता से भी सुलझाने की बात बार-बार कही। उसने जस्टिस कलीफुल्ला के नेतृत्व में श्री श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू की बाकायदा तीन सदस्यीय एक कमेटी बनाई, ताकि मेल-मिलाप से इस मसले का हल निकाला जा सके। जिस दिन इस कमेटी के गठन की बात कही गई थी, उस दिन अदालत में मैं भी मौजूद था। तब कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद दो पक्षों के बीच किसी जमीन की मिल्कियत का मसला भर नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र का एक अहम मामला है। इससे आम लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए मध्यस्थता से इसे सुलझा लिया जाए, तो बेहतर होगा। बुधवार को अंतिम सुनवाई में भी मध्यस्थता को लेकर बातें हुईं। अगर अंतिम फैसला आने से पहले भी मध्यस्थता से इस विवाद का हल

> राम जन्मभूमि मामले की जिस तरह सुनवाई हुई, वह केशवानंद भारती और इंदिरा साहनी जैसे मामलों के समान ही मील का पत्थर बनेगी।

निकल आता है, तो इसे काफी अच्छा माना जाएगा। इससे कोई पक्ष नाराज भी नहीं होगा। दरअसल, अदालत जब कोई फैसला सुनाती है, तो एक पक्ष को लगता है कि उसकी जीत हुई है और दूसरा उसमें अपनी हार देखता है। मगर मध्यस्थता की सफल प्रक्रिया में दोनों पक्ष जीतते हैं। ऐसे फैसले आम राय वाले माने जाते हैं।

अब अदालत पर यह कहकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं कि यहां न्याय पर आस्था भारी पड़ने लगी है। लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता। ऐसे मामलों में अदालत पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश देने का मुकदमा इसका अच्छा उदाहरण है। आज भी देश के असंख्य लोग यही मानते हैं कि औरतों को सबरीमाला मंदिर में पूजा करने का अधिकार देकर अदालत ने गलत किया। उसे ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। मगर अदालत क्यों न ऐसा करती? उसके सामने जो साक्ष्य रखे गए थे या जो रिकॉर्ड पेश किए गए, वे औरतों के हक की बातें कर रहे थे। यदि अदालत उस मामले में आस्था को तवज्जो देती, तो आज भी सबरीमाला मंदिर के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद होते।

सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि कोई मुकदमा आज दर्ज हुआ, और कल से ही उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। यहां मुकदमों की अहमियत सब कुछ तय करता है। अदालत अपना यह कर्तव्य समझती है कि उसका एक गलत फैसला कई चीजों को दांव पर लगा सकता है, जिसमें मानव-जीवन भी एक है। इसलिए वह सावधानी से सभी पक्षों की बातें सुनती है और सुनवाई पूरी करती है। हालांकि बुधवार को दलीलें पेश करते समय वकीलों का जो आक्रामक रुख सामने आया, उसे उचित नहीं कहा जाएगा। बतौर अधिवक्ता यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप अदालत की मर्यादा का उल्लंघन करें। अदालत की गरिमा का सम्मान करते हुए बहस की जानी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए।

यही वजह है कि न्याय-प्रक्रिया के लिहाज से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद भले खास हो, पर इसे कानून के हिसाब से ही तय किया जाएगा। संविधान पीठ साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाएगी। फिर भी यह इतना महत्वपूर्ण जरूर है कि इसे इंदिरा साहनी (आरक्षण की सीमा अधिकतम 50 फीसदी तय करने वाला मामला), सबरीमाला, केशवानंद भारती, निजता का अधिकार जैसे मुकदमों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसका फैसला भी देश-समाज पर व्यापक रूप से असरदार होगा और इसे नजीर के रूप में भविष्य में पेश किया जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

चर्चित चेहरा

नोबेल हकदार इथियोपिया का 'नेल्सन मंडेला'

अरुण नैथानी

आमतौर पर शांति के लिये दिये जाने वाले नोबेल पुरस्कार को लेकर यदा-कदा सवाल उठाये जाते हैं। खासकर राजनेताओं को लेकर तो राजनीति शुरू हो जाती है। फिर यदि वह किसी राष्ट्र की कार्यपालिका का मुखिया हो तो सवाल ज्यादा ही उठते हैं।?मगर इस बार नोबेल पुरस्कार जब इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया तो ऐसे सवाल नहीं उठे। उनके योगदान को मान्यता मिली है। उन्होंने खूनी संघर्ष से जूझ रहे देशों में शांति की बयार लाने का काम किया। इसमें पहल की और उसे अंजाम तक पहुंचाया। इसके लिये उन्हें देश का भूभाग तक गंवाना पड़ा, लेकिन संघर्ष के लिये चर्चित देश की जनता को वे मनाने में कामयाब हुए।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध और गरीबी से बेजार पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने बहुत कम समय में ही गरीबी, जातीय संघर्ष और अशांति से जूझते इथियोपिया को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया। उन्होंने इथियोपिया को ऐसा लोकतंत्र दिया जो हथियार के स्थान पर विचार को प्राथमिकता देने लगा है। उन्होंने बीते साल ही प्रधानमंत्री का पद संभाला है।

इथियोपिया के जिमा जोन में 1976 में जन्मे अबी अहमद के पिता मुस्लिम और माता ईसाई थी। वे कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे और कई विषयों में उन्होंने डिग्री हासिल की, ?जिसमें आदिस अबाबा विश्वविद्यालय से शांति व सुरक्षा में डावटरी की डिग्री भी शामिल है। इसके साथ ही लंदन स्थित ग्रीनविच वि.वि. से ट्रांसफॉरमेशनल लीडरशिप में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। उनका जीवन बदलाव के कई दौर से गुजरा। जीवन के शुरुआती वर्षों में वे इथियोपिया सरकार के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध में बतौर विद्रोही सैनिक शामिल हुए। वहां भी उन्होंने योग्यता का परिचय देते हुए कामयाबी हासिल की। संचार तथा खुफिया सेवाओं में उन्होंने महारत हासिल की और लेफ्टीनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। कालांतर उनकी भूमिका शांति अभियानों से जुड़ी और वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में रवांडा में भूमिका निभायी।

वे राजनीति में अचानक आए और शिखर की कामयाबी हासिल की। वर्ष 2010 में ओरोमो पीपुल्स डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने। कालांतर संसद सदस्य के रूप में चुने गये। बीते साल प्रधानमंत्री बनने के बाद अबी ने इथियोपिया का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया। इस देश की जो ताकत हिंसा व टकराव में लग रही थी, उसे उन्होंने देश के विकास में लगा दिया। सही मायनो में लोकतांत्रिक परंपराओं का पोषण किया। तानाशाही शासन में जेल में बंद हजारों लोकतंत्र समर्थकों को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद रिहा करवाया। निरंकुश सत्ता के भय से विदेशों में निर्वासित नेताओं को उन्होंने देश वापस आने का मौका दिया। अबी ने देश के भीतरी और बाहरी तनाव को भी कम किया।?जातीय समूहों को हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर दिया। मुस्लिम व ईसाइयों के बीच एक शांति विषयक फोरम बनाया।

इसी क्रम में अबी अहमद ने दशकों से पड़ोसी देशों से जारी खूनी संघर्ष को खत्म करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। दरअसल, एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच सीमा विवाद का संघर्ष दो दशक से लगातार चला आ रहा था। कभी इथियोपिया का ही हिस्सा रहे एरिट्रिया को विभाजन में मिले भूभाग को संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में हुए समझौते के बाद भी नहीं दिया गया था। जिसको लेकर दोनों देशों में खूनी संघर्ष? होते रहे हैं। अबी अहमद ने खुद शांति की पहल करते हुए हाथ बढ़ाया और एरिट्रिया ने उनका हाथ थाम लिया। अबी के प्रयासों से उच्च व्यावसायिक महत्व के केंद्र को एरिट्रिया के हवाले किया गया। दो दशक चले संघर्ष में करीब अस्सी हजार लोग मारे गये। अब दोनों देशों के बीच सीमा खुल गई है। इतना ही नहीं, अबी ने कई देशों के बीच जारी शत्रुता को टालकर शांति और सह-अस्तित्व का संदेश दिया। इरिट्रिया और जिबूती के विवाद तथा केन्या और सोमालिया के बीच समुद्री सीमा को लेकर जारी टकराव को भी अबी ने पहल करके खत्म कराया। यही वजह है कि अबी अहमद को इथियोपिया का 'नेल्सन मंडेला' कहा जाता है। असंभव से दिखने वाली जटिल समस्याओं को सुलझाने में उनकी भूमिका को देखते ही उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिये चुना गया।

निःसंदेह अबी को इस बात का श्रेय दिया जायेगा कि उन्होंने हिंसा-टकराव में खर्च हो रही ऊर्जा को रचनात्मक ऊर्जा में बदल दिया। उन्होंने न केवल निजीकरण को प्राथमिकता दी बल्कि उदारीकरण को अपनी नीतियों का आधार बनाया। यही वजह है कि आज इथियोपिया की गिनती सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में होती है। निःसंदेह इथियोपिया में असमानता, गरीबी और संघर्ष की जड़ें काफी गहरी हैं, बेरोजगारी अथाह है, मगर फिर भी इथियोपिया के लोग अबी अहमद में उम्मीद की किरण देखते हैं।

भूख सूचकांक

हालात सुधारने ही होंगे

नरपत दान बारहठ

आयरलैंड की एजेंसी ''कन्सर्न वर्ल्डवाइड' और जर्मनी के संगठन ''वेल्ट हंगर हिल्फे' द्वारा संयुक्त रूप से तैयार ताजा नियंतण्र भूख सूचकांक रिपोर्ट में भारत में भुखमरी के स्तर को ''गंभीर' बताया गया है। नियंतण्र भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2019 में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है जबकि उसके पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की रैंकिंग उससे बेहतर है। भारत पिछले साल 119 देशों में 103वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक की शुरुआत साल 2006 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी। वेल्ट हंगरलाइफ नाम के एक जर्मन संस्थान ने 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के तमाम देशों में खानपान की स्थिति का विस्तृत ब्योरा होता है, जैसे लोगों को किस तरह का खाद्य पदार्थ मिल रहा है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा कितनी है और उसमें क्या कमियां हैं। सोचने की बात है कि कृषि प्रधान देश भारत में आज भी भुखमरी बड़ी समस्या है। विकास की ओर अग्रसर देश में कई लोग भूख के कारण जान गंवाते हैं। हमारे देश में किसी भी विकासशील देश से अधिक कृषि योग्य भूमि है लेकिन कृषि के लिए पर्याप्त सुविधाएं इतनी नहीं है। संकट यह भी है कि छोटे-छोटे किसान अधिक आर्थिक लाभ कमाने के लिए खाद्यान्न फसल को छोड़कर नकद आर्थिक लाभ देने वाली फसल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कृषि में तकनीक का उपयोग पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए दुनिया में जितने भी भुखमरी के शिकार लोग हैं, उनमें से करीबन एक चौथाई भारत में रहते हैं। इस लिहाज से भारत को ''अलार्मिंग कैटेगरी' में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पैदा हुए कुल खाने का एक तिहाई कभी खाया ही नहीं जाता है यानि खाने का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में हर साल करीब 670 लाख टन खाना बर्बाद हो जाता है। इसकी कीमत करीब 50 हजार करोड़ है। देश की सार्वजनिक वितरण पण्राली की खामियों और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार ने लोगों को अकाल मौत मरने पर मजबूर कर दिया है। इसके जरिए वितरित होने वाले अनाज का 52 फीसद या तो वितरण, परिवहन और भंडारण व्यवस्था की खामियों के चलते नष्ट हो जाता है या फिर खुले बाजार में ऊंची दर पर बेच दिया जाता है। इसके अलावा पोषण से भरपूर और बेहतर क्वालिटी के खाद्यान्न खरीदने के मामले में आम लोगों की खरीदने की क्षमता भी भुखमरी पर काबू पाने की राह में एक प्रमुख बाधा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ऐसा भोजन खरीदने में सक्षम नहीं हैं। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी जितना खाना हम एक साल में बर्बाद करते हैं, ब्रिटेन तो उतना उगा भी नहीं पाता। हालांकि भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर राष्ट्र है, लेकिन फिर भी हमारे देश में भुखमरी के शिकार लोगों की तादाद चीन से भी अधिक हैं। भोजन के अपव्यय से बर्बाद होने वाली राशि को बचाकर करीब पांच करोड़ बच्चों के जीवन को बचाया जा सकता है। बड़ी अफसोस जनक बात है कि एक तरफ हम अपने घरों में, होटल में, घरों में या किसी शादी समारोह में बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है और वे भुखमरी का शिकार होते हैं। जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शासन का प्रमुख कर्तव्य है। बेहतर उत्पादन का वातावरण बनाने के साथ ही खाद्यान्न के बाजार मूल्यों को समुदाय के हितों के अनुरूप बनाए रखना होगा। देश को कृषि और खाद्यान्न सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने अनाज की विशेष मात्रा प्रदान करने की बजाय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि गांव खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अनाज के लिए लोग आत्मनिर्भर बनें। अन्न को बचाना और उसका सदुपयोग करना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। इसके लिए इच्छाशक्ति और अच्छी नीयत होनी चाहिए। इसके साथ हमें अपने संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का चिंतन करना चाहिए और अपनी आदतों में सुधार करना होगा। खाना सहेजने के लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं। न सिर्फ हम बल्कि बच्चे, परिजन, रिश्तेदार और मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें? इसके जो भी सकारात्मक नतीजे आएंगे, उसका फायदा किसी और को नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ही मिलेगा। अन्न बचाना ही जीवन बचाना है।

ग्रामीण इलाकों में एफएमसीजी बिक्री में गिरावट, उत्पादों की मांग 7 साल में सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली(एजेंसी)।

ऑटो और हीरा उद्योग को नुकसान पहुंचाने के बाद देश के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) सेक्टर पर भी आर्थिक मंदी के संकेत दिख रहे हैं। नीलसन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एफएमसीजी सेक्टर की विकास दर पिछले साल की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में आधे से भी कम रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी उत्पादों की मांग सात साल में सबसे कम रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एफएमसीजी बाजार ने 2019 की दूसरी तिमाही में 7.3 फीसदी की वैल्यू ग्रोथ हासिल की, जो कि पिछले साल की दूसरी तिमाही में हुई 16.2 फीसदी की बढ़त से काफी कम है। सात साल में ग्रामीण क्षेत्रों में भी एफएमसीजी की वृद्धि दर सबसे खराब रही है। 2018 की तीसरी तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी वृद्धि दर 20 फीसदी थी, जो इस साल दूसरी तिमाही में 5 फीसदी रह गई। शहरी क्षेत्रों में वृद्धि दर पिछले साल जुलाई-सितंबर में 14 फीसदी से गिरकर इस साल उसी अवधि में 8 फीसदी पर आ गई। कुछ कंपनियों का दावा है कि ग्राहक अब पांच रुपए वाले प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का कहना है कि उसके ट्रेड चैनल्स खासतौर पर होल सेलर्स और छोटे रिटेलर्स को नकदी की बड़ी दिक्कत हो गई है। इस वजह से 7 साल में पहली बार ग्रामीण बाजार में कंपनी के विस्तार में कमी दर्ज की गई है। एचयूएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवास पाठक ने बताया कि कंपनी इन बाधाओं को दूर करने के लिए सीधे रूप से हस्तक्षेप कर रही है।

सितंबर में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 20 फीसदी घटीः फाडा

नई दिल्ली(एजेंसी)।

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री सितंबर महीने में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.1 फीसदी घटकर 1,57,972 इकाई रह गई। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फाडा ने कहा कि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि त्योहारी मौसम शुरू होने पर कंपनियों द्वारा दी जाने वाली रियायतों के बावजूद वाहनों की बिक्री में गिरावट आई हो। एक साल पहले सितंबर, 2018 में वाहनों की बिक्री 1,97,653 इकाई रही थी। समीक्षाधीन अवधि में दोपहिया वाहन बिक्री 12.1 फीसदी घटकर 10,98,271 इकाई रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 12,48,998 इकाई थी। इसी प्रकार वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 18.5 फीसदी घटकर 63,518 इकाई रह गई, जो सितंबर, 2018 में 77,980 वाहन थी। हालांकि, इस दौरान तिपहिया वाहनों की बिक्री 1.8 फीसदी बढ़कर 55,553 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 54,560 इकाई रही थी। समीक्षाधीन महीने विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की कुल बिक्री 12.9 फीसदी घटकर 13,75,314 इकाई रह गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 15,79,191 इकाई रही। फाडा के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने कहा कि माह के दौरान खुदरा बिक्री दबाव में रही।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रचा इतिहास, 9 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू के साथ बनी देश की नंबर 1 कंपनी

बिजनेस डेस्क(एजेंसी)।

देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को नया इतिहास रचा। देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। शुक्रवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान जब रिलायंस के शेयर 2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,428 रुपए पर कारोबार कर रहे थे तो इसका मार्केट कैप 9.03 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। इससे पहले, अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था। आपको बता दें पिछले साल सरकारी कंपनी इंडियन आयल कार्पोरेशन ( ) को पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे अधिक आमदनी दर्ज करने वाली कंपनी भी बन गई है। पेट्रोलियम से लेकर, रीटेल और टेलीकॉम जैसे विभिन्न सेक्टर्स में फैली ने वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 6.23 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वहीं, आईओसी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में 6.17 लाख करोड़ रुपए का एकीकृत कारोबार किया। जबकि, आईओसी से दो गुना लाभ कमाकर देश की सबसे बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनी भी है शुक्रवार यानी आज ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के परिणाम आने वाले हैं। शेयर की कीमतों में उछाल से कंपनी ने यह नया मुकाम हासिल किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रिफाइनिंग मार्जिन सुधरने से रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमाई सितंबर तिमाही में अच्छी रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज ऐसी दूसरी कंपनी थी जिसका मार्केट कैप 8 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था। हालांकि, शुक्रवार को टीसीएस के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे और इसका मार्केट कैपप 7.66 लाख करोड़ रुपए था।

एयर इंडिया को बड़ी राहत, तेल कंपनियों ने टाला ईंधन की सप्लाई रोकने का फैसला

नई दिल्ली(एजेंसी)।

सरकारी तेल कंपनियों ने वित्तीय संकट से जूझ रही एयर इंडिया को ईंधन की सप्लाई रोकने का फैसला टाल दिया है। एयर इंडिया, इंडियन ऑयल (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। तेल कंपनियों का एयर इंडिया पर करीब 5000 करोड़ रुपए का बकाया है। एक अधिकारी का कहना है कि एयर इंडिया ने समय पर भुगतान करने का वादा किया है। इसलिए ईंधन सप्लाई रोकने के फैसले को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तेल कंपनियों के इस फैसले से एयर इंडिया को बड़ी राहत मिली है बता दें कि तीन सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने एयर इंडिया को भुगतान ना करने की स्थिति में 18 अक्टूबर से छह हवाई अड्डों पर उसे ईंधन सप्लाई रोकने की चेतावनी दी थी। इसकी वजह एयर इंडिया पर तीन कंपनियों का 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ईंधन भुगतान बकाया होना है। 22 अगस्त को आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पूरा भुगतान नहीं होने की वजह से कोच्चि, मोहाली, पुणे, पटना, रांची और विजाग के छह हवाई अड्डों पर एयर इंडिया को ईंधन की सप्लाई रोक दी थी।

संक्षिप्त समाचार

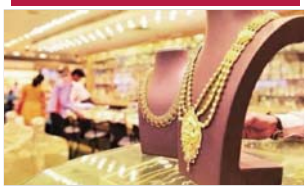

सोना 10 रुपए उतरा, चांदी स्थिर

नई दिल्ली। विदेशों में पीली धातु में रही नरमी और घरेलू स्तर पर डॉलर की तुलना में रुपए में रही मजबूती के बल पर दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 10 रुपए टूटकर 39,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और मांग सुस्त पड़ने के दबाव में चांदी 46600 रुपए प्रति किलोग्राम पर टिकी रही। लंदन एवं न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के अनुसार, सोना हाजिर 3.85 डॉलर उतर कर 1,488.60 डॉलर प्रति औंस के भाव बिका। दिसंबर का अमेरिकी सोना वायदा भी 1.30 डॉलर उतर कर 1,489.00 डॉलर प्रति औंस बोला गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी में नरमी रही। चांदी हाजिर 0.07 डॉलर गिरकर 17.45 डॉलर प्रति औंस बोली गई।

डीएचएफएल ने जारी किया पहली तिमाही का परिणाम, हुआ 242 करोड़ रुपए का घाटा

नई दिल्ली। कर्ज के बोझ में दबी आवास ऋण कंपनी डीएचएफएल को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 242.48 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है। इससे पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में कंपनी को 431.71 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। समीक्षावधि में कंपनी की कुल आय घटकर 2,399.84 करोड़ रुपए रही। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,154.25 करोड़ रुपए था। डीएचएफएल पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से भारी वित्तीय संकट से गुजर रही है। फरवरी, 2019 के बाद से कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में लगातार नीचे आ रही है।

दिवाली से पहले ईपीएफओ कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगा 60 दिन का बोनस

नई दिल्ली। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफओ के बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों को 60 दिन का दिवाली बोनस दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक ग्रुप बी और ग्रुप सी के सभी कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) स्कीम के तहत 60 दिन का बोनस दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा।प्रोडक्टॉ विटी लिंक्ड बोनस की 25 फीसदी राशि सीधे कर्मचारी के सैलरी खाते में जाएगी, जबकि बाकी 75 फीसदी राशि उसके पीएफ खाते में जमा होगी। बता दें कि इसके पहले सरकार ने सभी कर्मचारियों को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ पर 0.10 फीसदी की ब याज दर बढ़ा दी है। इसका मतलब कि सरकार बीते वित्त वर्ष के पीएफ पर 8.65 फीसदी की ब्याज देने वाली है। पहले यह ब याज 8.55 फीसदी की दर से मिलती थी।

वाहन कबाड़ सैंटर खोलने का रास्ता साफ, सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अधिकृत वाहन कबाड़ सैंटर (ऑथोराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी) खोलने का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसे वाहन कबाड़ सैंटर भी कहा जाता है। इस सैंटर को खोलने के लिए कुछ सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सियाम ने सरकार के इस कदम की सराहना की। हालांकि पुराने वाहन नष्ट करने पर ग्राहकों को छूट देने की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि अधिकृत कबाड़ सैंटर खुलने से देश में प्रदूषण करने वाले वाहनों को नष्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही नए वाहनों की डिमांड बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति वाहनों को नष्ट नहीं कर सकेगा। सरकार की तरफ से अधिकृत स्क्रैपर को एक डिजीटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो वाहन के नष्ट होने के बाद उसकी फोटो के साथ वाहन चैसी नंबर सरकार को देगा। सरकार नष्ट हुए वाहन का डाटा सरकारी डाटाबेस वाहन पर सुरक्षित रखेगी। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई व्यक्तिगत तौर पर फर्म सोसाइटी या फिर ट्रस्ट के जरिए वाहन कबाड़ सैंटर खोल सकता है। इसके लिए केन्द्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। बोर्ड की टीम सैंटर का दौरा करेगी और फिर सारे मानक पूरे होने पर एक अधिकृत लाइसैंस जारी करेगी। वाहन कबाड़ सैंटर खोलने के लिए स्थायी अकाऊंट नंबर और जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सैंटर के यार्ड में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना होगा।

अगले महीने से करोड़ों यात्री कर सकेंगे हवाई यात्रा, एयरलाइंस के बेड़े में बढ़ेंगे विमान

नई दिल्ली। एयरलाइंस के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ने जा रही है। दिसंबर तक करीब 20 से 25 विमान और शामिल होने से ज्यादा लोग हवाई सफर कर पाएंगे। डीजीसीए से मिली जानकारी के मुताबिक जेट एयरलाइंस के अचानक बंद होने से भारत में करीब 100 विमानों की कमी हो गई थी लेकिन अब एयरलाइंस के बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ने जा रही है। डीजीसीए ने उम्मीद जताई है कि दिसंबर तक बेड़े में 20 से 25 विमान के जुड़ने से विमानों की संख्या बढ़कर 625 तक हो जाएगी। इतनी संख्या होने के बाद हर महीने इन विमानों के जरिए 1 करोड़ 25 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। जेट के पास करीब 120 विमान थे, लेकिन इस एयरलाइंस के बंद होने से आधे विमान बाहर के देशों में चले गए और आधे विमान देश की एयरलाइंस कंपनियों ने खरीद लिए। जब जेट एयरलाइंस के विमान हवा में उड़ते थे तो भारत के पास 616 विमान थे, लेकिन एक बार फिर से अब भारत के विमानों की संख्या बढ़ रही है। अब भारत के पास 604 विमान हो गए हैं।

फ्लिपकार्ट, ऐमजॉन पर भारी छूट दिए जाने के आरोपों की जांच कर रही है सरकारः गोयल

नई दिल्ली(एजेंसी)।

सरकार भारी छूट के साथ बाजार बिगाड़ने वाली कीमत पर उत्पादों को बेचे जाने के आरोपों को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजन की जांच कर रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को विस्तृत सवाल भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है। गोयल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने पिछले एक पखवाड़े में अपने मंच से तीन अरब डॉलर का सामान बेचा है। आमतौर पर इन कंपनियों की सालाना बिक्री का आधा त्योहारी मौसम में ही बेचा जाता है। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट या रियायत देने और बाजार बिगाड़ने वाली कीमत की पेशकश करने का कोई अधिकार नहीं है। सस्ता सामान बेचकर खुदरा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां अपने पास उत्पाद रखकर उसकी बिक्री नहीं कर सकती हैं।

गोयल ने कहा कि उनके मंत्रालय को व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) से इन कंपनियों के कथित उल्लंघन की शिकायत मिली है। मंत्री ने कहा कि इन कंपनियों को विस्तृत सवाल भेजे गए हैं। आज या कल उन्हें अनुपूरक सवाल भी भेजे जाएंगे। गोयल ने याद दिलाया कि वह ई-कॉमर्स कंपनियों को पहले भी आगाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कानून स्पष्ट है। कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों के संगठन कैट ने सोमवार को गोयल को पत्र लिखकर ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यापार मॉडल की जांच कराने की मांग की थी। कैट ने यह भी कहा था कि फ्लिपकार्ट और अमेजन दावा करती हैं।

धनतेरस तक और बढ़ेंगे सोने के दाम, गोल्ड जाएगा 40000 रुपए के पार

नई दिल्ली(एजेंसी)।

करवाचौथ के बाद धनतेरस व दिवाली को देखते हुए ज्वैलरी मार्केट पूरी तरह तैयार हो गई है। खुशियों और दीपोत्सव का पर्व दिवाली पास आते ही मार्केट में भी रौनक दिखनी शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं दिख रही है तो वह है सर्राफा बाजार। इस बार सर्राफा बाजार में आपको दिवाली के दौरान कई तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं ताकि दिवाली पर आपकी खुशियां और भी बढ़ जाएं। धनतेरस भी ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत से लोग सोने में निवेश करते हैं। वैसे भी इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है लेकिन पिछले कुछ दिनों में सोने में इतनी तेजी आ गई है कि निवेशक इसमें नए निवेश को लेकर कनफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद सोने में गिरावट आ सकती है। धनतेरस के समय गोल्ड एक बार फिर 40,000 रुपए के पार जा सकता है। साथ ही इस बार सिल्वर की कीमत भी 49,000 रुपए प्रति किलो के करीब जा सकती है। हालांकि घरेलू मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं है मगर इंटरनैशनल लैवल पर गोल्ड और सिल्वर में बढ़ते निवेश के चलते दोनों के दामों पर दबाव बढ़ रहा है। धनतेरस के समय भारत में गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी सबसे अधिक होती है। एक अनुमान के अनुसार पूरे साल में गोल्ड और सिल्वर को जितनी खरीदारी होती है उसकी 30 प्रतिशत खरीदारी अक्तूबर से शुरू होने वाले फैस्टिव सीजन में होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि दिवाली तक गोल्ड में अनिश्चितता का माहौल रहेगा। ऐसे में गोल्ड में खरीदारी का यह वक्त सही है। दिवाली के कुछ दिन बाद शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा। इसके बाद गोल्ड फिर 40 हजारी बन सकता है। यानी गोल्ड की कीमत 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा सकती है। पवन गुप्ता का कहना है कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ घरेलू मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ नहीं रही है। मार्केट में गोल्ड की खरीदारी कम हो रही है। लोग अभी गोल्ड में निवेश करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं मगर गोल्ड की डिमांड दिवाली के 11 दिनों के बाद बढ़ सकती है। तब शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा। सोने की आसमान छूती कीमतें सोने की खरीद के आड़े आ जाती हैं। अगर आप भी दिवाली पर सोना खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है तो डिजीटल फॉर्म में सस्ते में शगुन की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन से ही फिजीकल यानी असली गोल्ड जैसा ही शुद्ध सोना डिजीटल फॉर्म में सुरक्षित रख सकते हैं। केडिया कमोडिटी के डायरैक्टर अजय केडिया का कहना है कि सोने में तेजी का ट्रैंड जारी रहने के लिए पर्याप्त फैक्टर बाजार में मौजूद हैं। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट वी. चंद्रशेखर का मानना है कि जो परिस्थितियां हैं

उनसे लग रहा है कि गोल्ड में तेजी रहेगी मगर वह एक सीमित दायरे में रह सकती है। हालांकि बीच में जब शादी-ब्याह का सीजन आएगा तो गोल्ड में तेजी कुछ समय के लिए ऊंचा लैवल छू सकती है। जहां तक सिल्वर का सवाल है तो चांदी में उतार-चढ़ाव का माहौल रहेगा।

धुली एवं कटी हुई प्लास्टिक बोतलों के कचरे के आयात पर रोक

नई दिल्ली। सरकार ने प्लास्टिक कचरे के बोझ को कम करने के उद्देश्य से धूली तथा कटी हुई प्लास्टिक बोतलों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। गैर सरकारी संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच (पीडीयूएसएम) ने शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उसके द्वारा दी गई प्रस्तुति के आधार पर यह प्रतिबंध लगाया है। भारतीय रिसाइकिल कंपनियां और कपड़ा उद्योग अवैध रूप से प्लास्टिक बोतलों के कचरे को फ्लैक्स के रूप में पाकिस्तान, बंगलादेश एवं अन्य देशों से आयात कर रहे थे क्योंकि यह रीसाइक्लिंग के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने की तुलना में सस्ता होता था। मंत्रालय के खतरनाक पदार्थ प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पीडीयूएसएम के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश प्लास्टिक कचरे के संग्रह और पुनर्चक्रण सिस्टम को मजबूत बनाने के तरीकों की तलाश में है। लेकिन रीसाइक्लिंग और कपड़ा उद्योग अपने लाभ के लिए अन्य देशों से प्लास्टिक कचरे का आयात कर रहे थे। आयात तंत्र में एक छोटी खामी के चलते भारतीय कंपनियां पेट बोतलों के कचरे को आयात एवं रीसाइक्लिंग करके विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग करते थे। वे इन पेट बोतलों को रीसाइकिल करके पॉलिएस्टर कारपेट, टी-शर्ट, एथलेटिक जूते, सामान, औद्योगिक स्ट्रैपिंग, ऑटोमोटिव पार्ट, सामान की रैक, फ्यूज बॉक्स, बंपर और डोर पैनल आदि का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका संगठन इन उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वे उत्पादों के विनिर्माण में स्थानीय स्तर पर उत्पादित प्लास्टिक कचरे का उपयोग करें, जिससे उनका व्यापार सुचारू रहे और वे देश को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में भी मदद कर सकें। शुक्ला ने कहा कि प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए बड़ी संख्या में मानव शक्ति की जरूरत है।

पीएमसी बैंक में 6500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, रिकॉर्ड से गायब 10.5 करोड़ कैश

मुंबई(एजेंसी)।

पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक में हुए घोटाले को लेकर जांच टीम ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच टीम को जांच के दौरान पता चला कि बैंक के रिकॉर्ड से कुल 10.5 करोड़ रुपए का कैश गायब है। पीएमसी बैंक की आंतरिक जांच कर रही टीम को जो चेक मिले हैं, उनको देखने से पता चलता है कि 10 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी इन चेक से की गई है। बाकी के 50 लाख रुपए का अभी तक कोई हिसाब नहीं मिल सका है। जांच टीम को घोटाले में आरोपी रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) और इसकी संबंधित कंपनियों द्वारा जारी किए गए कई चेक मिले हैं, जिसे कभी बैंक में जमा ही नहीं किया गया। बताया जाता है कि इन चेक को जमा किए बगैर ही उन्हें कैश दे दिया गया। जांच टीम के मुताबिक, दरअसल ये घोटाला 4,355 करोड़ का नहीं, बल्कि 6500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जांच से पता चलता है एचडीआईएल और उससे जुड़ी कंपनियां कैश चाहती थीं। उन्होंने पिछले दो साल में बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) जॉय थॉमस को चेक भेजे। थॉमस ने उन्हें चेक के बदले कैश दिए लेकिन उन्हें बैंक में जमा नहीं कराया। बैंक के रिकॉर्ड बुक में इन चेकों की कोई एंट्री तक नहीं है। इस जांच से पता लगता है कि 10 करोड़ के ऊपर जिस भी रकम का अब तक कुछ पता नहीं चला है, 10 करोड़ के ऊपर जिस भी रकम का अब तक कुछ पता नहीं चला है, उसे थॉमस ने अपने पास रख लिया था। गौरतलब है कि इस घोटाले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच की जा रही है। पीएमसी बैंक घोटाले में अब तक बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा, बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस, एचडीआईएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राकेश वधावन, उनके पुत्र सारंग वधावन और पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों की जांच में अभी इस घोटाले में और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं।

मंदी की भेंट चढा हिरा श्रमीक

एक साल से बेरोजगार हिरा श्रमीक ने की आत्महत्या

सूरत।

शहर में मंदी की वजह से बेरोजगारी और आर्थीक तंगी का सामना कर रहे एक के बाद एक हिरा श्रमीक आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर रहे है। अब तक कई हिरा श्रमीकों ने आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया है इसी तरह एक और घटना ने बेरोजगार हुए हिरा श्रमीक ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली।

जानकारी के अनुसार पूणागाम अर्जुन नगर विभाग दो निवासी 50 वर्षीय मगनभाई दुधात ने शुक्रवार दोपहर में घर की रसोई में फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी दोनों बेटी और एक बेटा अपने किसी परिजन के यहां गए थे इसी बीच उसने यह कदम उठा लिया। जब वह घर आये तो मगन फांसी पर झूल रहा था। पुलिस और 108 एम्बुलेंस को फोन किया। पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गई। मगन दुधात पिछले एक साल से बेरोजगार था जिस वह से उसकी दो बेटियां सिलाई कर घर का खर्च चला रही थी जबकि 13 वर्षीय बेटा पढाई करता है। बताया जा रहा है कि परिवार की स्थिति खराब होने से तनाव बड गया था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। वहीँ परिजनों का कहना है कि हिरा कारोबार में मंदी के कारण काम नहीं मिल रहा था। इस बात से भी वह तनाव में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दो कारों की भिड़ंत, वृद्ध की मौत

सूरत।

जिले के ताजपोर के निकट दो कारों के बीच हुई जबर्दस्त भिडंत में एक कार के वृद्ध चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सूरत जिले की बारडोली तहसील के वडोला गांव निवासी 65 वर्षीय बलवंत मिस्त्री अपनी पत्नी के साथ शेवरोलेट कार में बारडोली की ओर जा रहे थे। नवसारी-बारडोली रोड से गुजरते वक्त ताजपोर गांव के निकट बलवंत मिस्त्री के सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा। अचानक दर्द उठने पर मिस्त्री ने कार के स्टेयरिंग से नियंत्रण गंवा दिया और कार रोंग साइड में चली गई। उस वक्त सामने से आ रही स्विफ्ट कार और शेवरोलेट के बीच जबर्दस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में गंभीर चोट लगने से बलवंत मिस्त्री की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

गैंगस्टर रवि पुजारी सेनेगल से हुआ रफूचक्कर, भारत में दर्ज हैं 200 मामले

अहमदाबाद। गैंगस्टर रवि पुजारी सेनेगल पुलिस को भी चकमा देकर रफूचक्कर हो गया है। रवि पुजारी माफिया डॉन छोटा राजन का बेहद करीबी है। उसको लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। पुलिस ने स्वीकार किया है कि इसी साल सेनेगल में गिरफ्तार किया गया माफिया डॉन सड़क मार्ग से इस अफ्रीकी देश से फरार हो गया है। सूत्रों ने बताया कि रवि पुजारी सेनेगल में एंथनी फर्नांडिज के नाम से रहता था और खुद को बुर्कीना फासो का नागरिक बताता था। रवि पुजारी के खिलाफ पूरे देश में करीब 200 मामले दर्ज हैं। रवि पुजारी के खिलाफ गुजरात में दायर 26 मामलों की जांच कर रहे दो पुलिस अधिकारियों ने बताया, 'फरार गैंगस्टर रवि पुजारी कथित रूप से सेनेगल से भागकर किसी और अफ्रीकी देश चला गया है। कभी माफिया डॉन छोटा राजन का दाहिना हाथ रहे रवि पुजारी के खिलाफ भारत में फिरौती और हत्या के 200 मामले दर्ज हैं। इनमें से फिरौती के 26 मामले गुजरात में दर्ज हैं। पुजारी अक्सर गुजरात के बिल्डरों, पेशेवर लोगों, राजनेताओं और जूलर्स को फोन कॉल करके पैसे मांगता था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि पुजारी के निशाने पर गुजरात के 70 लोग थे।

पश्चिम रेलवे का दिपावली तोहफा

यात्रियों की सुविधा के लिए 15 और विशेष ट्रेनों की 82 सेवांए चलाई जाएंगी

सूरत।

पश्चिम रेल्वे द्वारा त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा बढाने के लिए तथा अतिरिक्त भीड़ को कम करने के मद्देनज़र पश्चिम रेलवे द्वारा 15 और विशेष ट्रेनों की 82 सेवाएँ चलाने का निर्णय लिया गया है।

जानकारी के मुताबीक ट्रेन सं. 82917 बांद्रा टर्मिनस-इलाहाबाद छेवकी साप्ताहिक सुविधा विशेष ट्रेन/ट्रेन सं. 09018 इलाहाबाद छेवकी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक हमसफर विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (4 फेरे)

ट्रेन सं. 82917 बांद्रा टर्मिनस-इलाहाबाद छेवकी साप्ताहिक सुविधा विशेष ट्रेन बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 00.20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 03.45 बजे इलाहाबाद छेवकी पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 एवं 30 अक्टूबर, 2019 को चलेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 09018 इलाहाबाद छेवकी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक हमसफर विशेष ट्रेन गुरुवार को इलाहाबाद छेवकी से 09.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 एवं 31 अक्टूबर, 2019 को चलेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान एवं पेंट्रीकार डिब्बे होंगे। यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, उधना, नंदुरबार, अमलनेर, जलगाँव, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर तथा शंकरगढ़ स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन सं. 09017/09018 बांद्रा टर्मिनस-इलाहाबाद छेवकी साप्ताहिक हमसफर विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (6 फेरे) ट्रेन सं. 09017 बांद्रा टर्मिनस-इलाहाबाद छेवकी साप्ताहिक हमसफर विशेष ट्रेन बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 00.20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 03.45 बजे इलाहाबाद छेवकी पहुँचेगी। यह ट्रेन 6, 13 एवं 20 नवम्बर, 2019 को चलेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 09018 इलाहाबाद छेवकी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक हमसफर विशेष ट्रेन गुरुवार को इलाहाबाद छेवकी से 09.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 7, 14 एवं 21 नवम्बर, 2019 को चलेगी। इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान एवं पेंट्रीकार डिब्बे होंगे। यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, उधना, नंदुरबार, अमलनेर, जलगाँव, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर तथा शंकरगढ़ स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन सं. 82929 बांद्रा टर्मिनस-गया जं. साप्ताहिक सुपरफास्ट सुविधा विशेष ट्रेन/ट्रेन सं. 09030 गया जं.-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट हमसफर विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (4 फेरे) ट्रेन सं. 82929 बांद्रा टर्मिनस-गया जं. साप्ताहिक सुपरफास्ट सुविधा विशेष ट्रेन शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 05.10 बजे रवाना होकर अगले दिन 14.00 बजे गया जं. पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 अक्टूबर एवं 2 नवम्बर, 2019 को चलेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 09030 गया जं.-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट हमसफर विशेष ट्रेन रविवार को गया जं. से 17.00 बजे रवाना होकर मंगलवार को 00.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 अक्टूबर एवं 3 नवम्बर, 2019 को चलेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान एवं पेंट्रीकार डिब्बे होंगे। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, चलथान, नंदुरबार, अमलनेर, जलगाँव, भुसावल, खंडवा, इटारसी जं., जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर, इलाहाबाद छेवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., सासाराम और डेहरी ऑन सोन स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन सं. 09029/09030 बांद्रा टर्मिनस-गया जं. साप्ताहिक सुपरफास्ट हमसफर विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (4 फेरे) ट्रेन सं. 09029 बांद्रा टर्मिनस-गया जं. साप्ताहिक सुपरफास्ट हमसफर विशेष ट्रेन शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 05.10 बजे रवाना होकर अगले दिन 14.00 बजे गया जं. पहुँचेगी। यह ट्रेन 9 एवं 16 नवम्बर, 2019 को चलेगी।

इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 09030 गया जं.- बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट हमसफर विशेष ट्रेन रविवार को गया जं. से 17.00 बजे रवाना होकर मंगलवार को 00.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 10 एवं 17 नवम्बर, 2019 को चलेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान एवं पेंट्रीकार डिब्बे होंगे। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, चलथान, नंदुरबार, अमलनेर, जलगाँव, भुसावल, खंडवा, इटारसी जं., जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर, इलाहाबाद छेवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., सासाराम और डेहरी ऑन सोन स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन सं. 8 2931 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जं. सुविधा विशेष ट्रेन/09032 बरौनी जं.-बांद्रा टर्मिनस हमसफर विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (4 फेरे) ट्रेन सं. 82931 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जं. सुविधा विशेष ट्रेन मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 12.55 बजे रवाना होकर गुरुवार को 02.30 बजे बरौनी जं. पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 एवं 29 अक्टूबर, 2019 को चलेगी। इसी प्रकार वापसी में 09032 बरौनी जं.-बांद्रा टर्मिनस हमसफर विशेष ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को बरौनी जं. से 05.55 बजे रवाना होकर अगले दिन 17.35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन 24 एवं 31 अक्टूबर, 2019 को चलेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान एवं पेंट्रीकार डिब्बे होंगे। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, उधना, नंदुरबार, अमलनेर, जलगाँव, भुसावल, खंडवा, हरदा, इटारसी जं., पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर, इलाहाबाद छेवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र और हाजीपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

ट्रेन सं. 09031/09032 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जं. हमसफर विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (4 फेरे) ट्रेन सं. 09031 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जं. हमसफर विशेष ट्रेन मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 12.55 बजे रवाना होकर गुरुवार को 02.30 बजे बरौनी जं. पहुँचेगी। यह ट्रेन 5 एवं 12 नवम्बर, 2019 को चलेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 09032 बरौनी जं.-बांद्रा टर्मिनस हमसफर विशेष ट्रेन गुरुवार को बरौनी से 05.55 बजे रवाना होकर अगले दिन 17.35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 7 एवं 14 नवम्बर, 2019 को चलेगी।

इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान एवं पेंट्रीकार डिब्बे होंगे। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, उधना, नंदुरबार, अमलनेर, जलगाँव, भुसावल, खंडवा, हरदा, इटारसी जं., पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, माणिकपुर, इलाहाबाद छेवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र और हाजीपुर स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन सं. 82907/82908 मुंबई सेंट्रल-लखनऊ जं. साप्ताहिक सुपरफास्ट सुविधा विशेष ट्रेन (6 फेरे) ट्रेन सं. 8 2907 मुंबई सेंट्रल-लखनऊ जं. साप्ताहिक सुपरफास्ट सुविधा विशेष ट्रेन गुरुवार को 19.35 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.40 बजे लखनऊ जं. पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 एवं 31 अक्टूबर तथा 7 नवम्बर, 2019 को चलेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 8 2908 लखनऊ जं.-मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट सुविधा विशेष ट्रेन शुक्रवार को 22.45 बजे लखनऊ जं. से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23.00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी।

जानगर शहर में डेंगू का कहर

जामनगर में डेंगू के मरीज की संख्या में बढ़ौतरी हुई

जामनगर में हररोज ५० से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे है बीमारी की रोकथाम के स्वास्थ्य विभाग के प्रयास जारी

जामनगर । जामनगर शहर में डेंगू का कहर जारी है। इस बीमारी के चलते शहर के सरकारी जीजी अस्पताल में ६४ और मरीजों की रिपोर्ट पॉजीटीव आई है। इस प्रकार दो दिनों में ही पॉजीटिव मरीजों की संख्या ११० हो गई है। दूसरी और ३० मरीजों की तबीयत में सुधार होने से उन्हें अस्पताल में छुट्टी दी गई है। हररोज ५० से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे है। अब तक ११ लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार जामनगर में बढ़ रही डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए अन्य जिलों की स्वास्थ्य टीमें भी जामनगर भेजी गई है, लेकिन डेंगू के मरीज की संख्या कम होने की बजाय बढ़ रही है। जीजी अस्पताल में ३४ घंटों के दौरान उपचार के लिए भर्ती हुए मरीजों में से ६४ की रिपोर्ट डेंगू पोजीटीव आई है। जिनमें से ३७ मरीज शहरी क्षेत्र के और १७ मरीज जामनगर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के है। यह आंकड़ा सिर्फ सरकारी अस्पताल के है, जबकि निजी अस्पतालों में भी डेंगू के अनेक मरीज उपचाराधीन है। अमरेली जिले के बगसरा में पिछले एक महीने से बुखार के मरीज बढ़ने लगे है, जिसमें डेंगू के मरीज भी शामिल है, जिनकी संख्या भी बढ़ रही है।

इस दौरान एक छह महीने के बालक की डेंगू से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बगसरा निवासी छह महीने के बालक को पिछले १० दिनों से बुखार आने के कारण अमरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से छ दिन पूर्व राजकोट के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई थी।

दीपावली के चलते बाजारों में पुलिस द्वारा चेकिंग जारी

अहमदाबाद । दीपावली त्योहार करीब है। ऐसे में बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली ग्राहकों की भीड़ के दौरान कोई अनहोनी घटना को रोकने के लिए शहर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने जांच शुरु की है। शहर के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके तीन दरवाजा, भद्र मंदिर के समीप एसओजी की टीम ने जांच की। इस दौरान निरधक दस्ते की टीम भी डॉग स्कवॉड के साथ तैनात रही। वह भी जांच कराते हुए दिखा दी। त्योहार को देखते हुए शहर पुलिस ने बैक, एटीएम, ज्वैलरी शोरूम और भीड़भाड़ वाली दुकानों के आसपास गश्त एवं पुलिस कर्मचारियों की तैनाती भी बढ़ाई है।

छात्राओं, दिव्यांगो को मिलेगी छूट

जीएसईबी द्वारा बोर्ड परीक्षा की फीस की घोषणा हुई

परीक्षा फीस में करीब दस फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई

अहमदाबाद । गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसईबी) की ओर से मार्च २०२० में ली जानी प्रस्तावित १०वीं और १२वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की फीस की घोषणा की गई है। इसमें गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्राओं और दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा फीस भरने से छूट दी गई है। परीक्षा फीस में करीब दस फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। जीएसईबी की ओर से घोषित की गई १२वीं विज्ञान संकाय की फीस के तहत नियमित विद्यार्थियों की फीस ६०५ रुपए है। एक विषय की परीक्षा देने वाले नियमित रिपीटर के लिए १८० रुपए, दो विषय की परीक्षा देने वाले रिपीटर नियमित छात्रय के लिए ३०० रुपए, तीन विषय की परीक्षा देने वाले रिपीटर नियमित छात्र के लिए ४२० रुपए और तीन विषय से ज्यादा की नियमित रिपीटर छात्र के रूप में परीक्षा देने वालों को ६०५ रुपए परीक्षा फीस भरनी होगी। प्रायोगिक विषयों की परीक्षा फीस प्रति विषय ११० रुपए निर्धारित की गई है। वह अलग से भरनी होगी। दसवीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा फीस २५५ रुपए निर्धारित की गई है। एक विषय दो और तीन विषय व उससे ज्यादा विषय की नियमित रिपीटर विद्यार्थी के रुप में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की फीस भी क्रमश: १३०, १८५ और २४० और ३४५ रुपए निर्धारित की गई है। निजी रिपीटर विद्यार्थी के लिए भी परीक्षा फीस घोषित की जा चुकी है। सामान्य संकाय की बोर्ड परीक्षा की फीस भी निर्धारित कर दी है। नियमित विद्यार्थियों के लिए १९० रुपए परीक्षा फीस निर्धारित की है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)